भारत के शैक्षिक परिवेश का एक अध्ययन

*मंजुल मयंक दीक्षित

सारांश

आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली के अपने अनेक मुद्दे और चुनौतियाँ हैं जिन्हें हल करने की आज परम आवश्यकता है ताकि बच्चें, जो देश का भविष्य हैं, को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ बदलाव भी देखा गया है लेकिन अभी भी कई खामियाँ और समस्याएँ हैं जिन्हें हल करने की महती आवश्यकता है। इस शोध पत्र में, मैंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के मुद्दों और चुनौतियों और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कुछ समाधानों पर विस्तार से चर्चा की है। देश भर में छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, संविधान ने छह मौलिक अधिकारों को प्रतिबद्ध किया, जिनमें से एक शिक्षा का अधिकार था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा प्रणाली को मुख्य रूप से पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है, जिसके बाद उच्च अध्ययन का चरण भी प्रारम्भ किया गया हालाँकि इस प्रणाली में कई कमियाँ और चुनौतियां हैं जिन पर सुधार किया जाए तो यह देश के समग्र विकास के लिए लाभदाई हो सकती है। भारत का शैक्षिक परिवेश सार्थक और आने वाली पीढियों का भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है।

मुख्य शब्द - : निःशुल्क शिक्षा, गुरुकुल, छात्र, चुनौतियाँ, शिक्षा प्रणली, पाठयक्रम, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि

प्रस्तावना आदिकाल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ अवस्था में रही है प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति भारतीय शिक्षा का मूल रही है। आरंभ से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था अपने समकालीन शिक्षा व्यवस्थाओं में अग्रणी और सदा से ही विकसित अवस्था में रही है । परंतु मध्यकाल आते ही मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ और इस शिक्षा व्यवस्था में अरबी,फारसी और उर्दू का बोलबाला रहा साथ ही राज काज की भाषा भी फारसी और उर्दू हो गई जिसके कारण लोग आजीविका के कारण इन भाषाओं को सीखने और सिखाने लगे धीरे–धीरे मदरसों की स्थापना होने लगी और इस्लामिक शिक्षा पद्धति का विकास होने लगा। राजा महाराजाओं के लिए राजमहल में शिक्षण व्यवस्था की जाने लगी। मध्यकाल के बाद शिक्षा ईसाई और व्यापारियों के हाथों में आ गई अब शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव दिखाई देने लगा शिक्षा व्यवस्था में ईसाई धर्म के साथ–साथ गणित,विज्ञान ,साहित्य आदि को आधुनिक पद्धति से पढ़ाया जाने लगा। शिक्षक विभिन्न वर्गों और विषयों का अध्ययन कराने लगे।अब रविवार और अन्य कई प्रकार के अवकाश घोषित होने लगे। अध्ययन की पद्धति अवधि के आधार पर होने लगी। शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई जिसने शिक्षा व्यवस्था में अनुदान तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का समावेश करने का सुझाव दिए साथ ही स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली को अपने संक्रमण काल में कई समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। मैकाले की शिक्षा पद्धति

द्वारा कई परिवर्तन किए गए जिससे गुरुकुल पद्धति जैसी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का समापन हुआ। कई अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों के कारण हमारी प्राचीन शिक्षण व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना हमारी भारतीय शिक्षण व्यवस्था को करना पड़ रहा है। इसे और भी स्पस्ट शब्दो में इस प्रकार समझा जा सकता है।

1 शिक्षा पर व्यय भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई लाभकारी कदम उठाए गए हैं और यदि ऐसा ही जारी रहा तो भारत जल्द ही मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकता है।

2 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाऐं गए सकल नामांकन पैटर्न को भारत द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए

3 क्षमता का उपयोग दुनिया को अब रचनात्मक दिमागों की जरूरत है और सरकार को स्कूलों को छात्रों को बढ़ावा देने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विचारों को अनसुना नहीं करना चाहिए।

4 बुनियादी सुविधाएँ विशेषकर सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चूंकि सरकार अब डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

5 पीपीपी मॉडल अच्छी तरह से डिजाइन किए गए पीपीपी भारत में स्कूल प्रणाली के लिए नवाचार के मॉडल बना सकते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को ध्यान में रखा जाना चाहिए

6 छात्र–शिक्षक अनुपात उचित शिक्षा की तलाश में छात्रों की संख्या उपलब्ध शिक्षकों और संकाय की तुलना में कहीं अधिक है। अतः देश के भविष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए

7 प्रत्यायन और ब्रांडिंग गुणवत्ता मानक

8 विदेश में पढ़ने वाले छात्र ऐसे कई छात्र हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन मुद्दों के कारण विदेश में पढ़ाई करना चुनते हैं। संबंधित अधिकारियों को उन पर काम करना चाहिए और छात्रों को भी भारत में रहने, सीखने और अपने ज्ञान के माध्यम से देश को सशक्त बनाने का विकल्प चुनना चाहिए।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याएँ एवं समाधान

कुछ सरल उपाय हैं जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की समस्याओं पर काबू पाने में मदद कर सकते है।

1 नवाचारों की आवश्यकता भारत डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। इससे देश के छात्रों और युवाओं के नवोन्मेषी दिमाग को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएगा और अधिकारियों तथा सरकार को युवाओं को केवल किताबी शिक्षा के बजाय समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

2 शिक्षा की गुणवत्ता देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर है। पूरे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि सभी को समान और निष्पक्ष ज्ञान और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें

3 शिक्षा को किफायती बनाना ऐसे सरकारी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान हैं जो किफायती हैं लेकिन बुनियादी ढांचे

और गुणवत्ता के मामले में उनमें कमी है। दूसरी ओर, कई निजी शिक्षा संस्थान हैं जो उच्च फीस की मांग करते हैं और उनके पास अध्ययन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और उपकरण हैं। इस असमानता पर काम किया जाना चाहिए और सरकार को शिक्षा को सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना चाहिए

भारत में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ और अभियान

1 सर्व शिक्षा अभियान 2001 में 'सभी के लिए शिक्षा' को बढ़ावा देने, स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नए स्कूलों के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

2 प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम – यह भारत सरकार का एक केंद्रित हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य "पहुँचने में सबसे कठिन" लड़कियों तक पहुँचना है, विशेषकर उन लड़कियों तक जो स्कूल नहीं जाती हैं।

3 मध्याह्न भोजन योजना यह एक ऐसा भोजन है जो सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत समर्थित सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), मदरसों और मकतबों में नामांकित सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है।

4 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यह एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाना और हर घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर नामांकन दर में वृद्धि करना है।

5 अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी।

6 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना।

भारत एक अरब से अधिक लोगों वाला देश है, और उनमें से केवल एक–तिहाई ही पढ़ सकते हैं। जनसंख्या का तेजी से बढ़ता आकार, शिक्षकों, पुस्तकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी, और शिक्षा लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त सार्वजनिक धन देश की सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ हैं।

आज की शिक्षा प्रणाली

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक क्लासिक 10.2 ढांचे का 5.3.3.4 शिक्षा प्रणाली के साथ प्रतिस्थापन है। 10 प्लस 2 साल की संरचना को त्यागकर, जो शिक्षण के रचनात्मक तरीके की ओर उन्मुख थी, नई शैक्षिक रणनीति माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिक समावेशी आधार स्थापित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए, 5 3.3 4 प्रणाली छात्रों को प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्ञान का आधार प्राप्त करने की अनुमति देती है और फिर वह रास्ता चुनती है जिसका वे बाद में स्कूली शिक्षा में पालन करना चाहते हैं, जिससे उन्हें पसंद की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। यह संशोधित रणनीति, बदले में, छात्रों को अपने कौशल और रुचियों को अधिक वैयक्तिकृत और वैयक्तिकृत तरीके से विकसित करने की अनुमति देती है, जिससे वे अपने आगामी भविष्य के प्रयासों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाते हैं। 5.3.3 4 शिक्षा प्रणाली क्या है? भारत की 5.3 3 4 शिक्षा प्रणाली के अनुसार, छात्रों के लिए कोई अतिरिक्त स्कूल वर्ष नहीं हैं। चूंकि एक बच्चे द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है, इसलिए भारी बोझ हल्का हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 5 3.3.4 शिक्षा पैटर्न के साथ, मानक 1 और 2 के साथ नर्सरी और किंडरगार्टन कक्षाओं को शामिल करती है, जबकि प्लेस्कूलों को

''औपचारिक शिक्षा'' के क्षेत्र में भी लाती है। यह दृष्टिकोण पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों और शैक्षणिक और व्यावसायिक हितों के बीच अंतर को कवर करता है। यह दृष्टिकोण एक अच्छी तरह से संरचित घर की तरह है, जिसमें एक ठोस नींव, दीवारें जो छत का समर्थन करती हैं, और छत तत्वों से एक सुरक्षात्मक परत प्रदान करती है। रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि समग्र शैक्षिक अनुभव के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। यह ठोस आधार एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां छात्र आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलता है।[1]

नई शिक्षा नीति उद्धरण आज तक, हम अपनी शिक्षा नीति में 'क्या सोचें पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं एनईपी में, हम 'कैसे सोचें' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं – नरेंद्र मोदी

संरचना 1. पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा और शिक्षण

1. नई अद्यतन शैक्षणिक संरचना जो पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को अलग करती है।

के चरण 2. 2 चरण 2. 4 चरण

आयु वर्ग 3. 6 से 18 वर्ष के बीच 3. 3 से 18 वर्ष के बीच

अवधि 4. स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष पूरे करें 4. 15 वर्ष (प्री–स्कूल के लिए 3 वर्ष और पूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 12 वर्ष)

5. ज्ञान को पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुँचाना। सभी स्तरों पर सभी के लिए स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। 5 .3 .3 4 शिक्षा दृष्टिकोण दर्शाता है कि प्रीस्कूल स्तर पर पहुंच, प्रवेश, जिम्मेदारी और सार्वभौमिकरण को बढ़ाने के लिए संपूर्ण स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की संरचना कैसे की जाए, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी प्रदान की जाए क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार के दृष्टिकोण का भी विस्तार करता है। 3 से 18 वर्ष की आयु वालों को शामिल करने के लिए अधिनियम। मौजूदा शहरी शिक्षा योजना के साथ तालमेल बिठाने के लिए, बच्चे प्लेस्कूलों में दाखिला लेते हैं, फिर उन स्कूलों में चले जाते हैं जहां वे दो साल की किंडरगार्टन कक्षाएं पूरी करते हैं और 12 साल के लिए स्कूल जाते हैं। सिस्टम को सरल बनाना यहां प्रत्येक वर्ग और आयु सीमा के लिए संपूर्ण औचित्य दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5 3.3.4 प्रणाली, छात्रों को मूलभूत चरण में 5 साल, प्रारंभिक चरण के तहत 3 साल, मध्य चरण में सीखने के 3 साल और अंत में माध्यमिक चरण में 4 साल बिताएंगे।

चरणों को बौद्धिक विकास के उन चरणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिनसे एक बच्चा प्रारंभिक बचपन, स्कूल और हाई स्कूल में गुजरता है।

यहां नई और सुधारित 5 3 3 4 शिक्षा योजना के विभिन्न चरणों का विवरण दिया गया हैः

मूलभूत मुख्य चरण

इस चरण में 5 वर्ष की अवधि शामिल है।

इसमें 3 से 8 साल की उम्र के छात्र शामिल हैं।

यह चरण प्रीस्कूल, आंगनवाड़ी, कक्षा पहली से तीसरी तक बनता है।

अंतर्गतराष्ट्रीय शिक्षा नीति, 3 साल की आंगनवाड़ी या पूर्वस्कूली शिक्षा के बाद दो साल का प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसमें कक्षा 1 और 2 शामिल हैं।

इस चरण का मुख्य फोकस भाषा विकास तकनीक और गतिविधि या खेल–आधारित शिक्षा होगा।

प्रारंभिक चरण

इस चरण में 3 वर्ष की अवधि होती है।

सीखने का यह चरण पूरी तरह से 8–11 पर केंद्रित है।

इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाएँ शामिल हैं।

गतिविधि–आधारित इंटरैक्टिव शिक्षा और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इस चरण के अंतर्गत आते हैं।

राज्य सरकार इस नई योजना के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए तीन भाषाओं को अधिकृत करेगी। शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका और पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषा प्राथमिक माध्यम होगी।

मध्य चरण

मध्य चरण में 3 वर्ष शामिल हैं।

इसमें 6वीं–8वीं तक की कक्षाएं शामिल हैं।

यहां, शैक्षिक प्रतिमान उस प्रतिमान में बदल जाता है जो निर्देश में लचीलेपन पर जोर देता है।

बच्चों को गणित, विज्ञान, कला और मानविकी की मूलभूत समझ हासिल होगी।

हमारी शैक्षिक प्रणाली में लंबे समय से उपयोग की जाने वाली रटने की पद्धति के विपरीत, एनईपी 2020 के 5 3 3 4 ढांचे का तात्पर्य है कि यह स्कूल शिक्षण स्तर आवश्यक सीखने के उद्देश्यों पर दृढ़ता से जोर देगा।[2]

माध्यमिक चरण

अंतिम चरण में 4 वर्ष शामिल हैं।

सीखने का यह चरण 14–18 वर्ष के आयु वर्ग को कवर करता है।

इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं शामिल हैं।

नीति छात्रों को पूरी तरह से अलग–अलग धाराओं में विभाजित करने को समाप्त करती है, जिससे उन्हें मल्टी–स्ट्रीम प्रणाली, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक पूल में भाग लेने की अनुमति मिलती है। एक छात्र अकाउंटेंसी और फिजिक्स के साथ इतिहास का चयन करके दो शैक्षणिक क्षेत्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को समाप्त कर सकता है। इस चरण का जोर कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक विषय चुनने की लचीलापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा छात्रों को उच्च शिक्षा में उनके द्वारा चुने गए विषयों या पाठ्यक्रमों को चुनने की सुविधा प्रदान करती है। पहले, विकल्प सीमित थे और छात्रों को पूर्व–चयनित पाठ्यक्रम चुनना पड़ता था। मसौदे के अनुसार, ''छात्र प्रमुख शैक्षणिक विषय संरचनाओं और अनुशासन के सिद्धांतों का ज्ञान विकसित करके और उस अनुशासन में जांच की

क्षमता विकसित करके उच्च शिक्षा में इस अनुशासन को आगे बढ़ाने के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।'' 9वीं से 12वीं कक्षा तक 8 समूह होंगे जहां छात्र स्कूल के अंतिम चार वर्षों में अपना पसंदीदा विषय चुन सकते हैं। मानविकी, गणित–कंप्यूटिंग, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और अंतर–अनुशासनात्मक विषयों को 8 श्रेणियों में बांटा जाएगा। 9वीं कक्षा से 12वीं तक के इन चार वर्षों को दो समूहों, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण (9वीं और 10वीं) में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी पढ़ाया जाएगा। जबकि दूसरे चरण (11वीं और 12वीं) में इतिहास, भौतिकी और भाषा विषयों का प्रशिक्षण होगा। 11वीं और 12वीं कक्षा (वर्ष में दो बार मूल्यांकन) के लिए सेमेस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी, जबकि 9वीं और 10वीं में मूल्यांकन के पिछले वार्षिक मोड का पालन किया जाएगा। इस प्रकार (पाठ्यक्रम) 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने के लिए छात्र को 16 पेपर पास करने होंगे। उन्हें तीन विषय समूहों में से आठ की सूची में से चार विषयों का चयन करना होगा। एनईपी 5334 कक्षाएं और परीक्षा पैटर्न नीति एक व्यापक रूपरेखा है, और इसकी सफलता के लिए इसकी कक्षा और परीक्षा पैटर्न आवश्यक हैं।[3] नीचे, हमने एक संरचना तैयार की है, जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो बताती है कि एक बच्चे की स्कूली शिक्षा यात्रा के दौरान कक्षाएं कैसे शुरू होंगीः 9वीं कक्षा तक मध्य चरण की तैयारी पर ध्यान दें: तैयारी और मध्य चरण में प्रत्येक कार्यदिवस की शुरुआत हमेशा 25 मिनट की सभा से होनी चाहिए। निम्नलिखित को 40 मिनट के खंडों में विभाजित किया जाएगा। यदि विषय के लिए ब्लॉक अवधि की आवश्यकता है, तो कक्षा 80 मिनट तक चलेगी। किसी अन्य विषय पर जाने से पहले, छात्रों को अपनी कक्षाओं की तैयारी के लिए 5 मिनट की संक्रमण अवधि मिलेगी। हालाँकि, शेड्यूल को 15 मिनट के स्नैक ब्रेक और 45 मिनट के लंच ब्रेक को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है। शनिवार को कोई सभा नहीं होगी और दोपहर का भोजन एक घंटे तक चलेगा। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तकः फिर, कार्यदिवस 25 मिनट की सभा के साथ शुरू होंगे। भले ही उनकी कक्षाएँ 50 मिनट तक चलती हैं, उनकी कुल कक्षा का समय 100 मिनट होगा। संक्रमण अवधि के दौरान छात्रों को अगले पाठ की तैयारी के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। भले ही लंच ब्रेक को 55 मिनट तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई अतिरिक्त जलपान का समय नहीं दिया गया है। शनिवार की सभाएं भी नहीं होंगी. इसके अलावा, इन कक्षाओं में एक अतिरिक्त संवर्धन अवधि भी होगी। परिणामस्वरूप अब छात्रों के पास लंबे स्कूल के दिन होंगे। यह छात्रों को पाठ्यक्रम विषय–वस्तु के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त समय का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है।

परीक्षा पैटर्न

एनईपी 2020 निर्दिष्ट करता है कि छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा में बैठेंगे। परिणामस्वरूप अन्य सभी वर्षों में मूल्यांकन एक नियमित और रचनात्मक प्रारूप में स्थानांतरित हो जाएगा जो महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषण और वैचारिक स्पष्टता सहित ''उच्च–स्तरीय कौशल'' की जांच करके ज्ञान और विकास को बढ़ाने के लिए अधिक ''प्रदर्शन–आधारित'' हो सकता है। 9वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं यह मौजूदा ढांचे का पालन करेगा।[4]

11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली होगी, जिससे छात्रों को तैयार महसूस होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी और छात्र उन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है या उनमें आत्मविश्वास महसूस करते हैं। नई शिक्षा नीति छात्रों को वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगी और उन्हें अधिक सार्थक और प्रभावी मूल्यांकन के साथ पोषित करेगी। छात्रों को वास्तविक दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल के साथ तैयार करके, वे कार्यस्थल में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। एक

अधिक सार्थक और प्रभावी मूल्यांकन उनकी प्रगति पर प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है और उन्हें सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस तरह, वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास हासिल कर सकते हैं और अपने काम में स्वामित्व की भावना विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने पर काम करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, रोल–प्ले या मॉक इंटरव्यू जैसी गतिविधियाँ छात्रों को अपने संचार और नेटवर्किंग कौशल विकसित करने में मदद कर सकती हैं, जो कार्यस्थल में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की गतिविधियाँ छात्रों को अपने पारस्परिक कौशल को निखारने की अनुमति देती हैं, जो करियर की सफलता का एक अनिवार्य घटक है। 5 3.3 4 शिक्षा के 6 लाभ नए शिक्षा मॉडल के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैंः अद्यतन मूल्यांकन योजना के अनुरूप ग्रेड 3, 5 और 8 में छात्रों के बुनियादी ज्ञान अधिग्रहण का मूल्यांकन करने के लिए 360^o प्रगति रिपोर्ट कार्ड का उपयोग किया जाएगा।[5]

नई एनईपी 2020 की 5 3 3 4 संरचना का उपयोग करके, बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की मुख्य दक्षताओं का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक शिक्षा में नामांकित करके, प्रस्तावित पहल विकास के महत्व पर जोर देती है। शोधकर्ता और चिकित्सक इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) बच्चे के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप, एनईपी 2020 की 5 .3.3.4 संरचना की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इसके दायरे में प्री–प्राइमरी को शामिल करना हो सकती है। छात्रों को सर्वोत्तम निर्णय लेने में मदद करने के लिए मजबूत कैरियर परामर्श सेवाएँ आवश्यक हैं क्योंकि नई स्कूल प्रणाली मध्य विद्यालय चरण में बहु–विषयक शिक्षा और विषय वस्तु विकल्पों को शामिल करती है। पसंदीदा विषयों को मिडिल स्कूल की शुरुआत से ही चुना जा सकता है, जिससे पेशेवर रूप से निर्णय लेने की जिम्मेदारी शिक्षकों या माता–पिता पर आ सकती है, जिन्हें ऐसा करने के लिए अधिक सक्षम होना चाहिए। इस उम्र में, छात्रों को आमतौर पर पेशेवर दुनिया की सीमित समझ होती है और वे आगे के अवसरों से अनजान हो सकते हैं। इसलिए, प्राधिकारी पदों पर बैठे लोगों को छात्र को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करने की आवश्यकता है। सारांश में 5.3.3 4 शिक्षा प्रणाली अब कोई रहस्य नहीं है। पारंपरिक 10.2 से लेकर नवीनतम 5.3 .3.4 शिक्षा मॉडल तक, शिक्षा मॉडल की संरचना का आधुनिकीकरण किया गया है। नई प्रणाली में छात्रों के विकास के प्रचुर अवसर हैं, जो स्कूलों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, स्कूलों और संस्थानों को एनईपी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी तरह से तैयार की गई सामग्री या अध्ययन सामग्री को अनिवार्य करना चाहिए। एकेडक्राफ्ट एनईपी–अनुमोदित सामग्री संरचनाओं को विकसित करने के लिए समर्पित है जो छात्रों के शैक्षणिक परिणामों, शिक्षकों की निर्देशात्मक दक्षता और संस्थान की विश्वसनीयता को प्रोत्साहित करती है। परीक्षा पैटर्न में भी संचयी संशोधन किया गया है। पैटर्न में नवीनतम बदलाव में, बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य अवधारणाओं और ज्ञान अनुप्रयोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य सीखने और सिखाने के मॉडल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ले जाना है। शिक्षण सभी हितधारकों को शिक्षा प्रक्रिया में बाध्य करने के लिए शिक्षा अवसंरचना समाधान और स्कूल ईआरपी और एलएमएस घटकों का एक समूह प्रदान करेगा।[6]

निष्कर्ष भारतीय शिक्षा प्रणाली आदिकाल से लेकर वर्तमानकाल तक कई स्तरों से होते हुए अग्रसर हुई है।विभिन्न कालखंडों में इसके अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आदिकाल से आधुनिककाल तक कई परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। गुरुकुल पद्धति से आज आधुनिक शिक्षापद्धति तक कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारत सरकार की कई योजनाओं तथा नवाचारों द्वारा इसमें कई सुधार भी देखने को मिलते हैं।इन योजनाओं से जहां शिक्षा व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ हुआ है वहीं छात्र छात्राओं के नामांकन में भी

वृद्धि हुई है। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है ।

***सहायक आचार्य**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय, रूपवास

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत की वर्तमान शिक्षा एवं समाज व्यवस्था में मैकाले प्रभाव पृष्ठ 11
2. 18वीं सदी में दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएँ भारत में थीं (भारतीय शिक्षा) पृष्ठ 79
3. भारत में शिक्षा का विकास (vivacepanorama) पृष्ठ 12
4. Evolution of educational thought in India (लेखक – भँवर लाल द्विवेदी) पृष्ठ 34
5. Education in Karnataka through the ages by Jyotsna Kamat पृष्ठ 89
6. भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास (अच्युत कुमार) पृष्ठ 78